

सं० ओ० वि०/यानो०/५-८७/१३८५१.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रबन्धक निदेशक, कोन्फेड, सेंक्टर २२-बी, एस. सी. ओ. १०१४-१५, चण्डीगढ़, (२) जनरल मैनेजर कोन्फेड, करनाल के श्रमिक श्री रमेश सिंह पुत्र श्री दया सिंह सं० नं० ३०६, आर्य नगर सोनीपत, तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ; और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ३(४४)८४-३-अम, दिनांक १८ अप्रैल, १९८४ द्वारा उक्त अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला, को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री रमेश सिंह की सेवाओं का समापन/छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

दिनांक ३ अप्रैल, १९८७

सं० ओ० वि०/रोह०/३९-८७/१३९६९.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० श्री राम सन्येटिक्स फैब्रिक्स एम.आई.ई., ३२९, बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री बिन्देश्वरी, पुत्र श्री रामनवल प्रसाद भार्फत श्री पोलू राम पंवार, मकान नं० ३२२, वार्ड नं० १४, पुराना झरर रोड, बहरा कवाड़ी के सामने, बहादुरगढ़ जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिनियम सं० ९६४१-१-अम ७८/३२५७३, दिनांक ६ नवम्बर, १९७० के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री बिन्देश्वरी की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह०/३९-८७/१३९७६.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० श्री राम सन्येटिक्स फैब्रिक्स एम.आई.ई., ३२९, बहादुरगढ़, (रोहतक) के श्रमिक श्री धीरेन्द्र, पुत्र श्री उग्रानन्द भार्फत श्री पोलू राम पंवार, मकान नं० ३२२, वार्ड नं० १४, पुराना झरर रोड बहरा कवाड़ी के सामने, बहादुरगढ़, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७, की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ९६४१-१-अम/७८/३२५७३, दिनांक ६ नवम्बर, १९७० के साथ गठित सरकारी अधिसूचना की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उस से नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री धीरेन्द्र की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं० ओ० वि०/रोह०/३९-८७/१३९८३.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० श्री राम सन्येटिक्स फैब्रिक्स, एम.आई.ई. ३२९, बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री चिरंजी लाल, पुत्र श्री झांजू राम भार्फत श्री पोलू राम पंवार, मकान नं० ३२२, वार्ड नं० १४, पुराना झरर रोड, बहरा कवाड़ी के सामने बहादुरगढ़, जिला रोहतक तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा १० की उपधारा (१) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० ९६४१-१-अम-७८/३२५७३, दिनांक ६ नवम्बर, १९७०, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा ७ के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री चिरंजी लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?